भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2824
दिनांक 18 मार्च, 2025 / 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सली गतिविधियां और हिंसा

†2824. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दस वर्षों के दौरान नक्सलवाद के विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारण नक्सली गतिविधियों एवं हिंसा में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और देश के प्रभावित राज्यों को प्रदान की गई सहायता/सुविधाओं तथा कार्यों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मुद्दे पर चल रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" को मंजूरी दी थी। उक्त नीति के अंतर्गत एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सुरक्षा के उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल था।

सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, प्रशिक्षण सुविधा, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियां, हथियार एवं उपकरण, आसूचना के आदान-प्रदान, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सहायता करती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2824, दिनांक 18.03.2025

• सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के तहत सुरक्षा बलों की परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं से संबंधित आवर्ती व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए राज्यों द्वारा किए गए व्यय, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों और प्रचार सामग्री आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 2014-15 से 2024-25 के दौरान इस योजना के तहत 3260.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

• विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के तहत राज्य खुफिया शाखाओं (SIBs), विशेष बलों, जिला पुलिस और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराया जाता है। SIS के तहत 1741 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत 221 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है और कुल 621 FPSs का निर्माण किया गया है।

• इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (ACALWEM) योजना के तहत 2014-15 से 2024-25 के दौरान हेलीकॉप्टरों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 1120.32 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास के मोर्चे पर, प्रमुख योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है।

• सड़क संपर्क के विस्तार के लिए 14,607 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं।

• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 7,768 टावर लगाए गए हैं।

• कौशल विकास के संबंध में, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और 49 कौशल विकास केंद्र (SDCs) कार्यात्मक बनाए गए हैं।

• जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRSs) को क्रियाशील बनाया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2824, दिनांक 18.03.2025

• वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5731 डाकघर खोले हैं। 1007 बैंक शाखाएँ और 937 एटीएम खोले गए हैं और सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 37,850 बैंकिंग पत्राचार (BC) चालू किए गए हैं।

• विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) के तहत, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3563 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के फलस्वरूप वाम पंथ उग्रवाद हिंसा की घटनाएँ जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर यानी 1936 तक पहुँच गई थी, 2024 में घटकर 374 रह गई यानी 81 प्रतिशत की कमी आई। इसी अवधि में कुल मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) की संख्या में भी 85 प्रतिशत की कमी आई है यानी 2010 में 1005 मौत से घटकर 2024 में 150 रह गई।

पिछले 10 वर्षों के दौरान, वाम पंथ उग्रवाद हिंसा की घटनाएँ जो 2014 में 1091 थी, 2024 में घटकर 374 रह गई यानी 65.7 प्रतिशत की कमी आई। इस अवधि में कुल मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) की संख्या में भी 52 प्रतिशत की कमी आई है यानी 2014 में 310 मौत से घटकर 2024 में 150 रह गई।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। अप्रैल 2018 तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 90 रह गई है, जुलाई 2021 तक 70 और फिर अप्रैल 2024 तक 38 रह गई है।

*****